

## प्रपत्र-4

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य।

### संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 10-2-2016 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सलमान हुसैन, वन बीट अधिकारी, राजस्व विभाग की ओर से श्री कुण्डल राम, राजस्व उपनिरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मनीष खड़ायत, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.8435 हे0, वन पंचायत भूमि शून्य हे0 एवं नाप भूमि 0.180 हे0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग के ग्राम गाजरी, रूनड़ा की 41.2 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 50 व नाप भूमि पर 6 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....

सहायक अभियन्ता ( )  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0  
अस्कोट (पिथौरागढ़)

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह0/- राजस्व उप निरीक्षक  
(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)  
पिथौरागढ़

ह0/- (वन विभाग का प्रतिनिधि)

अधीक्षक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0  
अस्कोट (पिथौरागढ़)

(जिलाधिकारी)

(प्रभागीय वनाधिकारी)

ह0/-

(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)

तहसीलदार  
कनालीडीना पिथौरागढ़  
ह0/-  
उप जिलाधिकारी  
डीडीहाट  
जिला- पिथौरागढ़  
उत्तराखण्ड

वन क्षेत्र अधिकारी  
डीडीहाट वन क्षेत्र

जिला अधिकारी  
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF  
(for the forest land to be diverted under FCA)**

5.1 A proposal has been received by this office from E.E PWD Askote for diversion under FCA-1980) of 1.8435 hac. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Chadandev-Nwali To Runra Moter Road. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated..23.9.2016

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 1.8435 hac.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. :- Yes

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- No

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

Not Required

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. Hence the proposal recommended for acceptance.

(Signature)

Place:- Pithoragarh

Date..27-9-2016

Name - Dr

(Vijay K. Bhargava)

Designation.....

प्रदेशीय वन अधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

Office Seal .....

N.B.

x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.